[Shri Hari Vishnu Kamath].

history. The scheme was subsequently abandoned.

It is needless for me to add that Western Court is one of the finest landmarks in New Delhi, and its architecture has been compared by many European visitors to that of the magnificent historic Acropolis of Athens in Greece.

I am sorry to say that its maintenance and repair over the years have been very poor, and if this can be geared up vigorously, I have no doubt that it will continue to be a good hostel for M.Ps. and others till even the end of this century.

14.02 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80—Contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION—contd.

MR. CHAIRMAN: We now take up further discussion and voting on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

Shri Anantram Jaiswal may continue his speech. He has taken 14 minutes already. He may try to wind up in two or three minutes.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): How many hours ramain?

MR. CHAIRMAN: One hour and 30 minutes is the balance, time left, out of which the Minister will take about an hour.

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद): सभापति महोदय, पिछले दिन मैं बोल रहा था कि सरकार की तरफ़ से हमेशा यह आंकड़े पेश किये जाते रहे कि अन्न की पैदावार बढ़ रही है। बढ़ी भी है। लेकिन उसी के साथ साथ जो दूसरी बात छोड़ दी गई वह यह कि जहां एक तरफ़ अन्न की पैदावार बढ़ी वहां दूसरी तरफ़ जनसंख्या भी बढ़ी है और जिसका नतीजा यह है कि प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धि जो है उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ दाल की खपत घटी है दूध का कहीं नाम नहीं है। तो इस तरह की कमियों का दुष्परिणाम यह है कि हमारा पोषण नीचे गिर गया है और जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनमें बायलाजिकल डिफ़ोरमिटी शुरू हो गई है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जब कभी अन्न की पैदावार के बारे में बात की जावे तब दो, तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये।

(1) दो तिहाई हमारी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है, प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धि नही है, और कम से कम नीचे के जो 6, 7 करोड़ लोग है उनको मुश्किल से चार छटाक अन्न आज भी मिलता है और जहां तक कैलोरीज का सवाल है करीब डेढ हजार कैलोरीज का हमारे यहां औसत होगा जब कि सम्पन्न देशों में ढाई से तीन हजार कैलोरीज लोगों को मिलती हैं। इसकी वजह से बायलाजिकल डिफ़ोरमिटी शुरू हो गई है। जब यह चीजें आयें तो एक तड़प होनी चाहिये सरकार और उसके आदमियों में कि खाने पीने के मामले में कितने पीछे दुनिया मे हम हैं।

एक दूसरी चीज मैं और जोर देकर कहना चाहता हूं कि पैदावार एक दफे बढ़ जाती है फिर घट जाती है और इसी तरह फिर बढ़, और घट जाती है। अभी तक यह सिलसिला रहा हैं कि हम पिछली उपलब्धि को नहीं बचा पाते। इस पर जब गौर किया जाता है तो अन्त में एक ही चीज समझ में आती है कि पानी की व्यवस्था नही है। अभी तक हमारी पूरी खेती लायक जमीन को पानी नहीं मिल पाता है, मुश्किल से एक-चौथाई जमीन के सिंचाई के साधन हैं। 1 करोड़ 70 लाख

का जो छठी योजना मे लक्ष्य रखा है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हू कि यह लक्ष्य बहुत कम है। इतना लक्ष्य तो एक साल के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये, अगर इसको हासिल करना है। उसमे भी जो पुराने तरीके हैं, उनको छोड दिया गया है। कभी बडी सिंचाई, कभी मध्यम सिंचाई और कभी छोटी सिंचाई कर दिया जाता है। आजकल छोटी सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है। साधारण किसान को मतलब नही कि किस तरह से सिंचाई हो रही है, उसके खेत को तो पानी मिलना चाहिये। 30 साल का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक तीन-चौथाई जमीन सिंचाई के लिये बाकी है। इस चीज को हमेशा ध्यान मे रखना चाहिये।

इधर एक और मुसीबत है। एक तरफ आप कहते हैं कि अनाज की पैदावार रिकार्ड है, दूसरी तरफ अन्न के भडार पहले से ही भरे है। मै जानना चाहता हू कि बढे हुए पैदावार को कहा रखा जायेगा? उसके लिये अगर सोच-विचार या इमैजीनेशन होता तो पहले से ही यह समझा जाता कि ज्यादा गोदामो की जरूरत है और इसके लिये नये बजट की शुरुआत के लिये नही बैठे रहना चाहिये था, बल्कि उसके निर्माण की कार्यवाही बहुत पहले शुरु हो जानी चाहिये थी। इसमे भी गफलत हुई है कि समय रहते गोदाम बनाने की कोशिश नही की गई। 360 करोड रुपये वर्ल्ड बैंक से मिले है, मै जानना चाहता हू कि उसका कितना उपयोग हुआ? उससे काम की शुरुआत हुई कि नही? मै चाहूगा कि जब मत्री महोदय अपने वक्तव्य के लिये खडे हो, तो इन चीजो की जानकारी दें। अभी तक जितने गोदाम बने हुए है वह शहर-अभिमुख हैं, किसान-अभिमुख नही रहे हैं। किसान के काम का जो क्षेत्र है, गोदाम उनके निकट बनने चाहिये। यह चीज ध्यान मे रखनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा किसान की जगह से गोदाम की जगह मे 10 किलोमीटर से ज्यादा का अन्तर नही हो। खाली उसको डाइवर्ट करना है। बडे-बडे गोदामो की जगह छोटे छोटे गोदाम बनाये जाने चाहिये।

तो गोदाम भी नही बनाये गये और साथ ही साथ बोरे भी नही है। यह चीज कितने जोरो से कही कि घर नही, जगह नही, बोरे नही तो यह अनाज कहा कहा जायेगा? मैं जानना चाहता हू कि यह किस की साजिश है कि इतने बडे पैमाने पर अनाज को बर्बाद किया जा रहा है?

कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल (मेहसाना) हमारे यहा 500 मन गेहू तो सड गया है।

श्री अनन्त राम जायसवाल इसमे आपके विभाग की तरफ से कमी यह रही हैं कि पहले से कोई सोच-विचार नही किया गया कि इसके लिये बोरे चाहिये तो कहां से आयेंगे। किसान अब त्राहि-त्राहि करता है कि न जगह है, न बोरे है, साथ ही साथ रेलवे मे पूरा टोटल कोलैप्स है, वैगन नही मिलते, चाहे आलू की पैदावार हो अन्न की पैदावार हो, कोयला पहुचाना हो या खाद पहुचानी हो, किसी भी चीज के लिये आज वैगन नही मिल रहे है। कम से कम 25, 30 फीसदी खाद अभी भी बाहर से मगाना पड रहा है। हमारे यहा नामरूप का फर्टिलाइजर का कारखाना इसलिये बन्द हो गया कि उनकी पैदावार को रखने के लिये भी गोदाम की जगह नही है और खाद को दूसरी जगह ले जाने के लिये वैगन नही है। यह सब क्या हो रहा है और कौन इसके लिये जिम्मेदार है? कोई कहेगा कि बहुगुणा जी जिम्मेदार है, कोई किसी किस्म का को-आर्डिनेशन नही दिखाई पडता। मैं चेतावनी देना चाहता हू कि स्टील का प्रोडक्शन घट गया, सीमेंट मिलेगा नहीं गोदाम बनाने के लिये, वैगन मिलेंगे नही, डालडा के दाम बढ रहे है और मिट्टी का तेल नही मिल रहा है। मैं आने वाले

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

सभा की ओर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा था कि महंगाई सिर्फ़ एक परसेंट बढ़ेगी। लेकिन पिछले एक महीने में महंगाई तीन परसेंट बढ़ चुकी है। प्राइस इन्डेक्स में तीन पायंट्स की वृद्धि हो गई है। इस तरह एक परसेंट के बजाये तीन परसेंट महंगाई पहले ही बढ़ गई है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकारी कर्मचार मंहगाई भत्ते की मांग करेंगे, जनता में रोष होगा, जरूरत की चीजें उचित मूल्य पर बाजार में नहीं मिलेंगी। इस से असंतोष पैदा होगा, जिसका सामना अगले चार छः महीनों में सरकार को करना पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि सरकार के विरोध में ऐसे लोग है, जो राजा लोग हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वर्ना अब तक विरोध खड़ा हो गया होता।

मैंने शुरू में एक तस्वीर रख कर कहा था कि खेती में बहुत पूंजी लगाने की जरूरत है कुछ लोग यह उपाय बताते है कि किसान की उपज के दाम बढ़ा दिये जायें यह नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश की राष्ट्रीय आय का एक-तिहाई हिस्सा एक फ़ीसदी बड़े लोगों के हिस्से में चला जाता है। और बाकी दो-तिहाई पूरे देश को मिलता है। खेती में जो लोग काम कर रहे है, उनकी आय पांच, साढ़े पांच रुपये के आस-पास है। जब देश की यह हालत है, तो खेती में लगाने के लिए पूंजी का निर्माण असंभव है। किसान का सहारा लेने से यह नहीं हो सकता है।

सरकार एक उपाय जानती है कि टैक्सों को बढ़ा दिया जाये या डेफ़िसिट फ़िनांसिंग कर दिया जाये। 1976 से मनी सर्कुलेशन 60 परसेंट के आस-पास और बढ़ा दिया गया। उसके अलावा अधिक निवेश के लिए सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं है।

तीसरा उपाय मैं बताता हूं। हमारे किसान नेता चाहेंगे कि खेतिहर की उपज के दाम बढ़ाये जायें। जब उनके दाम बढ़ाये जाते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। लेकिन इससे कोई सुधार नही होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खेतिहर की उपज के दाम बढ़ाने के बजाये कारखानों की चीजों के दाम घटाये जायें, उनपर से एक्साइज ड्यूटी और टैक्स हटा कर उनके दाम गिराये जायें और दामों के रिश्ते में एक संतुलन कायम किया जाये। अभी तक कपड़े, चीनी, मिट्टी के तेल और औजारों के दामों तथा खेती की उपज के दामों में इस तरह का कोई रिश्ता नहीं है। अगर एक चीज का दाम बढ़ेगा, तो दूसरी का दाम भी बढ़ता चला जायेगा। सभी चीजों के दामों में अभी तक कोई संतुलन नही रहा है। इसलिए खेती के दामों को देखते हुए कारखाने की चीजो के दाम घटाने की कोशिश करनी चाहिए।

जहां तक बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने का सम्बन्ध है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था और मैं फिर पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि सरकार किफ़ायतशिआरी करे और बड़े लोगों के खर्च पर पाबन्दी लगाये। यह अच्छी बात है कि माननीय वित्त मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जो सरकारी फ़िजूलखर्ची की जाच करेगी और उसको रोकेगी। लेकिन इस बारे में जल्दी होनी चाहिए। सरकार फ़िजूली और फ़िजूलखर्ची दोनों को रोके। इससे सरकार को पूंजी-निवेश के लिए पैसा मिलेगा और शायद वह खेती का विकास कर सकेगी। सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास की योजना, ब्लाक स्तर पर सघन विकास की योजना और मरुस्थल, रेगिस्तान के विकास की योजना आदि जो योजनायें बनाते गई हैं, वे बहुत सुन्दर है और उनके तहत काम होना चाहिए, लेकिन उनके लिए पूंजी नहीं है। इन योजनाओं को पीसमील ढंग से लागू किया जा रहा है। जैसे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ़ एक जिले मिर्जापुर में—और पूरे मिर्जापुर में

भी नहीं, उसके एक-आध ब्लाक में समन्वित ग्रामीण विकास योजना चालू की गई है। इससे देहात का विकास नहीं हो सकता है। पढ़ने में ये योजनायें अच्छी हैं, उनमें लफ्फाजी अच्छी है, लेकिन उनसे विकास नहीं हो पाता है। मंत्री महोदय देश की असली तस्वीर को—उपभोक्ता और किसान दोनों की तस्वीर को सामने रख कर इस बारे में विचार करें। लोगों को उनसे बहुत आशा है, क्योंकि वह खेती की समस्या से अच्छी तरह से अवगत है। हमारे पुराने दोस्त इस वक्त है नहीं, उत्तर प्रदेश असेम्बली में वह हमारे साथ-साथ थे और जब बोलते थे तो जिस दर्द और जज्बात के साथ बोलते थे सरकार के काम में भी वह जज्बात रहें तो अच्छा होगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई हिन्दुस्तान के जीवन और संस्कृति का अंग है। मैं फिलहाल जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारी अनाज की पैदावार बढ़ी है, इस के लिए देश आभारी है, हमारे देश में अनाज का अच्छा स्टाक है इस से देश में बहुत बड़ा संतोष है। सिंचाई के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है, इसकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा। लेकिन हमारी खेती का असल सवाल जो आजादी की लड़ाई से शुरू हुआ था, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि उस सवाल को जानबूझ कर के समाप्त कर दिया गया है। वह सवाल यह था कि हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो उसमें एक यह लक्ष्य था कि हम ग्राम के गरीब को जमीन देंगे और जमीन केवल उन के पास रहेगी जिनका धन्धा खेती होगा। लेकिन आज तक पिछले सारे समय में कांग्रेस सरकार जमीन के सवाल को निरन्तर उठाती तो रही मगर उठाने के बाद हिन्दुस्तान के छोटे किसानों को भूमिहीनों को कुछ मिला हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ने थे उस समय हम ने एक योजना कमेटी का विचार किया था और हमें आशा थी कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तब भूमिसीमा निर्धारित कर के कम से कम दस करोड़ एकड़ जमीन ऐसी ले लेंगे जिस को हम छोटे किसानों और भूमिहीनों में बांटेंगे। आजादी की लड़ाई के बाद पहली पंचवर्षीय योजना पर जब हम ने विचार किया उस समय हम ने यह अनुमान लगाया था कि देश के अन्दर 5 से लेकर 8 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी होगी जो भूमिहीनों में बांटी जा सकेगी। लेकिन आज हालत यह है, मैं उस सारे प्रकरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन एमर्जेंसी के समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगायी और उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें यह वादा किया था कि हम देश के बड़े-बड़े किसानों से 40 लाख एकड़ भूमि लेकर भूमिहीनों में बांटेंगे। मगर श्रीमती इंदिरा गांधी एमर्जेंसी लगाने के बाद भी न कोई ज्यादा जमीन ले सकीं और न उस को भूमिहीनों में बांट सकीं।

कांग्रेस का जो इतिहास रहा हो, वह रहा मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस जनता पार्टी का मैं भी सदस्य हूं, उस जनता पार्टी की सरकार ने भूमि के सवाल पर या तो बिल्कुल चुप्पी साध ली है या बिल्कुल उस की अवहेलना कर दी है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम ने 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बांट दी है लेकिन मैं उन से साफ जानना चाहूंगा कि जनता सरकार बनने के बाद कितनी जमीन राज्यों में अधिग्रहण की गई है? ये जिस जमीन का हिसाब दे रहे हैं यह जमीन वह नहीं है जो जनता सरकार के जमाने में अधिग्रहण की गई है। असल बात यह है कि जानबूझ कर या अनजाने जो दूसरे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जनता पार्टी साहूकारों की और पूंजीपतियों की पार्टी है, यह सरकार उस आरोप को अपने आचरण से अपने आप सिद्ध करती चली जा रही है और आज मुझे अफसोस है कि खास तौर के जहां-जहां जनता सरकारें हैं चाहे हरियाणा ले लें, गुजरात ले लें या पंजाब ले लें, वहां

[श्री रामकिशन]

लेश मात्र भी काम इस दिशा में नहीं हुआ है, बल्कि जो थोड़ा बहुत काम हुआ था उस को भी समाप्त कर दिया गया है। जिन किसानों को जमीन दी गई थी उस जमीन को छीना जा रहा है। तो माननीय कृषि मंत्री जी सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाएंगे, खेती की पैदावार बढ़ेगी लेकिन जिस वादे को लेकर हम यहां आए सामाजिक न्याय देने के लिए और गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने के लिए, मैं चाहता हूं कि या तो अपने घोषणा-पत्र से इस शब्द को हटा दें या कम से कम मेहरबानी कर के जैसे कांग्रेस ने समाजवाद को बदनाम किया वैसे ही जनता पार्टी भी अपने आचरण से इस शब्द को बदनाम न करे जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां इस का उपयोग करना चाहें तो कर लें। मैं समझता हूं इस मामले पर सरकार को खास तौर से जोर देना चाहिए।

आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या गांवों मे गरीबों की है। दो करोड से ज्यादा भूमिहीन मजदूर है जिनकी जिन्दगी का सहारा नही है। इसी तरह से छोटे किसान भी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसका निराकरण आगामी सालों मे हमारी जनता सरकार को करना है, वह है भूमि वितरण का सवाल। मै जानना चाहता हूं क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई दृढ़ इरादा है ? क्या आप राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रभावित कर सकेंगे ?

दूसरा बडा सवाल देश में किसानों पर कर्जे का है। आज देश के छोटे किसान जिनके पास चार एकड़ से कम जमीन है और जो भूमि-हीन मजदूर हैं उन पर 40–50 अरब का कर्जा है। इतने पैसे की ही उन्हें हर साल जरूरत होती हैं। संगठित क्षेत्र में जो बैंकें अथवा कोआपरेटिव सोसायटीज हैं वे 10–11 परसेंट से ज्यादा नहीं देती हैं। पुरानी सरकार ने छोटे लोगों पर कर्जा माफ करने की बात कही थी लेकिन यह सरकार उस बात को भूल गई। इस भयंकर शोषण से गांवों के गरीब को बचाने की आवश्यकता है। जिन लोगों को वहां कर्जे की जरूरत है उनके लिए कर्ज का प्रबन्ध होना चाहिए। आज जिस प्रकार से ग्रामीण धनी किसान और साहूकार गरीबों को लूट रहे हैं उस तरफ जनता सरकार की नजर नहीं जा रही है। आर्थिक कार्यक्रम तभी सफल हो सकते है जबकि राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम उनके साथ जुड़ जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारी जड़ें कमजोर हो जायेंगी और दस साल में गरीबी बेरोजगारी हम तभी मिटा पायेंगे जबकि दस साल तक हम शासन में रहेंगे। इसके लिए हमें आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के नारे देने होंगे और कार्यक्रम बनाने होंगे। इस मोर्चे पर मैं जनता पार्टी को उत्साहवर्धक नहीं मान सकता ; इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

आज मैं आंकड़ों के चक्कर में न जाते हुए कहना चाहता हूं कि इस समय सबसे बड़ा सवाल कीमतों का है। जैसा कि अनन्तराम जी ने जिक्र किया, इमरजैन्सी लगाने के बाद दावा किया गया था कि कीमतें नीचे गई और कुछ दिनों के लिए नीचे गई भी लेकिन उस समय आप देखेंगे कि खेती से उत्पादित चीजों के दाम 28 परसेंट गिरे थे जबकि कारखानों की चीजों में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है कि खेती की पैदावार के दाम निरन्तर गिर रहे है और कारखानों की चीजों की कीमतें ऊंची जा रही है। इस सरकार में ऐसे लोग हैं जो कि डा० लोहिया की दाम नीति के प्रशंसक थे लेकिन आज वे चुप हैं। मैं नहीं समझता किस प्रकार से यह सरकार जनता को न्याय दे पायेगी। जब तक सरकार कीमतों तथा गरीब भूमिहीन मजदूरों का सवाल हल नहीं करेगी तब तक इस देश में खेती का विकास सम्भव नहीं है। आज हमारे पास अनाज का बहुत बड़ा भण्डार है लेकिन आज जो खपत

है और जो जन्म दर है उसके हिसाब से अगले 25 साल में इस देश की जनसंख्या एक अरब हो जायेगी और उस समय इस आधार पर 25 करोड़ टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार को आज नहीं बल्कि अगले 15–20 साल में देश की क्या तस्वीर होगी उस पर ध्यान देना चाहिए।

मन्त्री जी ने दावा किया है कि पिछली सरकार के मुकाबले में अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की हैं लेकिन आज भी 70 प्रतिशत भूमि कुदरत के भरोसे पर है। हमारे कुछ छोटे-छोटे पड़ौसी देशों ने तो शत प्रतिशत जमीन पर सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया है। यदि हम छोटे किसानों को थोड़ी जमीन देकर भी पानी की व्यवस्था कर दें तो वे अधिक पैदा कर सकते हैं। मिसाल के लिए आप फार्मोसा को ही ले लें —मैं वहां पर राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा—आप कोरिया को ले लें, वहां 6–8 एकड़ का किसान जितनी पैदावार लेता है उतनी पैदावार हमारे देश में 50–60 एकड़ का किसान भी नहीं ले पाता। जिन प्रणालियों को अपना कर वहां पर हर एक खेत पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है, हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। मेरी राय में बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के स्थान पर छोटी योजनायें हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी खेतों में पानी का प्रबन्ध करना चाहिए। अगर ये चीजें हो जायेंगी, तब हम समझेंगे कि हमारी सरकार भूख और गरीबी के सवाल को मिटाने के लिये सही दिशा में चल रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कोई अच्छा काम ह नही किया है, लेकिन पिछले तीन सालों में मौसम भी हमारे इतना अनुकूल रहा है, जिस की वजह से हम सुखद स्थिति में है। लेकिन यदि एक-आध साल मौसम ने झटका दे दिया, तो यह सरकार सम्भाल नहीं पायेगी। इस लिये जरूरत इस बात की है कि हम अल्पकालीन और दीर्घ-कालीन उपाय करें। अल्पकालीन उपायों के लिये सरकार थोड़ा-बहुत चिन्तन कर रही है, लेकिन दीर्घ-कालीन उपायों तथा समानतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में जाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं—भूमि सुधार के मामले में जब तक आप तेजी से कदम नही बढ़ायेंगे, तब तक यह सरकार 10 सालों तक नहीं टिक सकेगी। यदि दस सालों तक टिकना है तो भूमि सुधार के कार्यक्रम को हाथ में लेना होगा।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी राम गोपाल सिंह (बिल्हौर) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कानपुर की कुछ गम्भीर समस्याओं की तरफ़, जहां किसान का शोषण हो रहा है, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं है कि बिजली, पानी, खाद तथा बीज की व्यवस्था करके सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है और किसानों ने भी अधिक परिश्रम करके उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे हमारा देश अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो गया है। यह बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है। साथ ही सरकार ने ग्राम-विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये अधिक धन निर्धारित किया है, किन्तु हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार होने के कारण उस राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है और किसानों की माली-हालत ही सुधर सकी है। इसके कुछ अन्य कारण भी है।

जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो दाम घटता है और जब उत्पादन घटता है तब दाम बढ़ जाते है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो पाता है। इससे उनका मनोबल और उत्साह गिरता है। पिछले साल अन्न की यही हालत हुई और इस साल आलू की हालत भी यही हुई। हमारे पूर्व-वक्ताओं ने आलू का

[चौधरी राम गोपाल सिंह]

भाव 25 रुपये या 30 रुपये प्रति-क्विंटल बताया है लेकिन यह भाव मण्डियों का है, जहां पर पहुंचने में 15 या 16 रुपये प्रति क्विंटल खर्चा पड़ जाता है। बहुत से लोग पैसे के अभाव मे बारदाना भी नही खरीद सके हैं, उनका आलू खेत मे ही पड़ा-पडा सड रहा है। भ्रष्टाचार होने के कारण साधारण किसान कोल्ड-स्टोरेज मे भी आलू नही रख पा रहा है। यदि यही हालत चलती रही और सरकार कोई व्यवस्था नही कर सकी, तो आलू 2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकेंगा और उसका लाभ साधारण किसान को न होकर बडे लोगों को होगा।

कृषि में अनेक दैवी-प्रकोप होते रहते है, खास तौर से तिलहन और दलहन मे, जिसके कारण किसानों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इसीलिये इन फसलों को बोने मे किसान रुचि नही ले रहे है, जिसके कारण दालें बाजार में 5 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं, जबकि किसानों को उनका लागत मूल्य भी नही मिल पाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार इन फसलों की रक्षा के लिये कोई उपाय निकाले ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

सरकार किसानों को ट्यूब-वेल आदि के लिये ऋण देती है, लेकिन वे ऋण सीधे किसानों को न देकर किसी डीलर के नाम दिया जाता है, जिससे किसानो को अधिक कमीशन देनी पड़ती है। यही हालत गाय-भैंस के खरीदने से भी होती है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि किसानों को पूरे-का-पूरा ऋण या अनुदान मिल सके। एक समस्या मेरे कानपुर की है जो कि मेरे क्षेत्र मे आता है। वहां पर कानपुर के निकट शहरी विकास हेतु जो भूमि सन् 1967–68 मे अर्जित करने हेतु नोटिस दिये गये थे, उसका सरकार ने अभी तक न तो कब्जा लिया और न मुआविजा दिया और इस भूमि को नगर महापालिका अब कब्जे में ले रही है। इससे कुछ किसानों को पुराने रेट पर 1200 रुपये से 1800 रुपये तक प्रति एकड़ की दर से मुआविजा दे रही है और जो सम्पन्न किसान थे, जिन्होंने इसके खिलाफ़ कुछ आपत्ति प्रकट की थी और मुकदमे दायर किये थे, उनको 30 हजार प्रति एकड़ की दर से मुआविजा दिया जा रहा है और जो ग़रीब किसान है, उनके साथ बडा ही अन्याय हो रहा है क्योंकि उनको सिर्फ 25 पैसे प्रति गज के हिसाब से मुआविजा मिल रहा है जबकि नगर महापालिका 200 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन बेच रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह के अन्याय को समाप्त किया जाए। जो बेरोजगार किसान हो गये हैं, जिनकी जमीन छीनी जा रही है, वे अकेले घर मे रह कर क्या करेंगे। इन को एक समान मुआविजा दिलाया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा जाए कि यह असमानता क्यों बरती जा रही है। किसी को 1200 रुपये एकड़, किसी को 1800 रुपये एकड़ और किसी को 30 हजार रुपये एकड़ मुआविजा दिया जा रहा है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जो लोग मुसीबत में फसे हुए है, उनको बचाने के लिये वे तुरन्त कार्यवाही करे। इसी क्षेत्र मे जो भूमि कृषि योग्य है, उसमे एक अर्बन सीलिंग एक्ट लागू कर दिया गया है जबकि इस एक्ट का उपयोग शहर के अन्दर बडे-बडे बगले व अहातों में पड़ी हुई खाली भूमि को लेने हेतु था न कि कृषि योग्य भूमि जिस पर खेती हो रही है। इस एक्ट के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि पर मुकदमे चला कर ली जा रही है और किसानों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है और इस क्षेत्र से आबपाशी, सिचाई का रेट भी दुगना कर दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ट्रेक्टरो से खेती करना सम्भव नही है, जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों मे बंटती जा रही है जिसके कारण बैलों द्वारा ही खेती करना सम्भव है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है

कि गौहत्या पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए ताकि खेती का कार्य सुचारु रूप से चल सके और पौष्टिक पदार्थ भी समाज को मिल सकें।

अन्त में मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी की सिफारिश करे, तो उस पर अमल न किया जाए क्योंकि मन्त्री जी ने यह कहा था कि कुछ प्रतिनिधिगण इस प्रकार की सिफारिश करते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करे ताकि भ्रष्टाचार दूर हो, तभी समाज का और किसानों का कुछ कल्याण हो सकता है वरना हमेशा इस प्रकार हम लोग चिल्लाते रहेंगे और न समाज का कोई लाभ होगा और न किसानो की गरीबी दूर हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आनरेबिल मिनिस्टर।

SHRI PURNANARYAN SINHA (Tezpur): You have given 20 to 30 minutes to so many Members. You have to allot time regionwise. I have not been given a chance to speak on this subject.

सभापति महोदय : अब समय समाप्त हो चुका है, अब मिनिस्टर साहब बोलेंगे। I am not in a position to give you time.

SHRI PURNANARYAN SINHA (Tezpur): You can extend the time.

MR. CHAIRMAN: I am sorry it cannot be done.

(Interruptions)

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब, आप बोलिये, देखिये, कृपा करके आप सब बैठ जाइए। यह मेरे हाथ की बात नहीं है। I have already called the Minister and the Minister will speak

श्री उग्रसेन (देवरिया) : आप संसदीय मन्त्री जी को बुला कर बात कर लें। हमने लिख कर दिया है। आप एक घंटा और बढ़ा दीजिए और सबको पांच, पांच मिनट बोलने के लिए दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है, जिस पर हम बोलना चाहेंगे।

सभापति महोदय : आप मिनिस्टर आफ़ पालियामेंटरी एफ़ेयर्स के पास जाकर बात कर लें।

I have called the Minister; I am not going to change. The Minister.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): Madam Chairman, I am very thankful to the hon. Members who have participated in the debate in the Demands for Grants of my Ministry and have shown a lot of interest in the subject as usual. I am also thankful to the chair for allotting maximum time from the Demands of this Ministry. At the same time, I am sorry that still some of the hon. Members have not been able to participate in the debate and they are now expressing their regrets

श्री उग्रसेन : हम लोगों को भी सुन लेते थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा होता। हम लोगों के भी कुछ अधिकार हैं... (व्यवधान)

सभापति महोदय: जनता पार्टी के होकर आप मिनिस्टर को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिये।

श्री उग्रसेन : हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सुन कर जवाब दें।

सभापति महोदय : बारह घंटे डिबेट इस पर हो चुकी है। और समय नहीं बढ़ सकता है।

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: More than sixty hon. Members have participated in the debate and they

[SHRI SURJIT SINGH BARNALA —Contd.]

have raised various points. Because of limitation of time, it will not be possible for me to reply to all the points that have been raised here. My colleague, Shri Bhanu Pratap Singh, while intervening had covered many points; I will be covering some of the other points which were not replied by him.

I have gone through the points made during the debates on the subject relating to the earlier years and have found that the trend of debate has now changed. A couple of years before, the emphasis in the debate was on the shortages of production, shortages of availability of foodgrains in some parts of the country and also high prices in the free open market for agricultural produce. In some areas, there were problems of availability of foodgrains due to various reasons. So, always the emphasis had been on these matters. But now, I find that the thrust of the debate has changed entirely. No, the complaint is mainly regarding the insufficient prices being paid to the farmers, not regarding the availability of foodgrains in any part of the country but regarding the surpluses in some parts and the complaint is that because of these surpluses, the prices go down; this happens whenever there is larger production of certain agricultural items. A mention was made regarding potatoes; a lot of discussion has been going on regarding sugarcane, cotton and other items. I think, all this has happened because of increase in agricultural production in the country. That is a very happy and healthy sign.

I am also happy to note that several hon. Members have underlined the importance of remunerative pricing of agricultural commodities and in fact, it is only the foundation of remunerative pricing policy on which the edifice of scientific agriculture can be built up.

Many of the hon. Members mentioned about the Agricultural Prices Commission; they criticised the Commission saying tha their terms of reference should be changed and these should be made more realistic. I may inform the hon. Members that we are considering suitable changes in the terms of reference of the Agricultural Prices Commission. We have constituted a Committee headed by Dr. S. R. Sen to go into the refinement of the procedures adopted for calculating the cost of production of the principal agricutural commodities under differing growing conditions.

And an integrated input-output pricing policy is essential. At the same time, we should do nothing which would lead to a rise in prices of principal commodities to such an extent that consumption is adversely affected. What we need urgently is a widening of the consumer base so that we are not faced with uncomfortable glut of agricultural produce, whenever there is an improvement in the production. I would, therefore, like to assure the hon. Members that is will be my constant endeavour to develop and promote a public policy package which would help to stimulate simultaneously production as well as consumption.

The hon. Members know that because of certain policy regarding sugar, the consumption of sugar in the country has increased during the last two years; and it is not a minor increase. From about 37.5 lakh tonnes in 1976-77, we are hoping that the consumption will reach about 60 lakh tonnes; and our total production now is only 65 lakh tonnes. We are to export about 6.5 lakh tonnes. Inadditiona buffer stock of about 5 lakh tonnes is also to be created. So, we will be consuming some sugar from the stocks of the previous year. That is necessary for maintaining a balance. Just now my hon. friend was mentioning what will happen if the prices soar higher. How this is a problem again, Madam Chairman. If

the prices of sugar are kept at a certain level, at a comportable level, then the prices of sugar cane fall. If the prices of sugar-cane are slightly pitched up, then the prices of sugar go up. That is why we have to adopt this policy; and it was due to the fact that most of the hon. Members were asking about it.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I am not telling about the failure: I am telling about the remunerative prices

MR CHAIRMAN: Let him complete first. Then you can ask questions.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Last time when the debate was going on, a large number of Members from both sides were asking that the control on sugar should go. Now they should not at all be complaining about this, because of the control having been removed The prices of sugar came down, but they came down to such an extent as was not a healthy trend for the production of sugar. Now if the sugar prices are maintained at about Rs. 2.70 or Rs. 2.80 or something like this, then it will be possible to run the sugar mills properly and also pay suitable prices for the cane growers.

As our agriculture advances, we will have greater responsibility for enlarging both internal and external agricultural trade. I may inform the hon. Members that the Task Force for making suggestions regarding export was constituted in the Department; and from their report, which was a thorough report, it has been estimated that there is a possibility of exporting Rs. 3100 crores worth of agricultural produce in the near future instead of the present Rs. 1848 crores. Action has been initiated to implement the major recommendations of this Task Force. I may also inform the House that the export will not be done at the expense of the home consumption but will rather be designed to promote consumption through greater opportunities for gainful employment also

Recently, when Janata Government came into power, a lot of groundnut extraction was being exported with the result that the price of groundnut extraction in the country was Rs. 2000 a tonne. There were lots of complaints for poultry farmers, dairy farmers because cattle feed was selling at a very high price. So, we initiated some control measures; and I am happy to inform the hon. Members that the prices of groundnut extraction came down; and it was brought down to about Rs 1000 per tonne from Rs. 2000 per tonne. And since that time, we are having good reports from the poultry farmers, dairy farmers and feed manufacturers. And the feed is easily available. So, at the cost of internal consumption, we do not intend to have export. But we will have export considering the requirement, in the country.

Regarding the achievements during the year 1977-78, my hon. friend Shri Bhanu Pratap Singh also pointed out that it was a record crop. Commendable advance was in rice production which went to a peak of 52.7 million tonnes, exceeding the previous highest level by 4 million tonnes. This gave us a new hope because earlier advance had been made only in wheat production, not rice production. A lot of advancement has been made in jowar production also which was 11.8 million tonnes and it was 1.4 million tonnes higher than the peak level reached during 1974-75. In respect of commercial crops also, 1977-78 was significant as compared to the previous year. Production of cotton in 1977-78 was higher by 21.6 per cent, of oil seeds, which are in short supply even now by 13.2 per cent, of sugarcane by 18.7 per cent. The overall index of agricultural production in 1977-78 at 132.7, was 13.9 per cent higher than the previous year.

[Shri Surjit Singh Barnala]

May I now take the opportunity to share with the hon Members available information on preliminary assessment of production levels in respect of foodgrams, cotton, jute, oilseeds, etc. during 1978-79. In spite of losses to the tune of three million tonnes of foodgrains due to floods and excessive rains and hailstorms during the last kharif season the total output in the current year is expected to be around 127 million tonnes.

Regarding cotton also the output is expected to reach a record level of 75-76 lakh bales, jute and mesta production at 81 lakh bales is 13.4 per cent higher than last year, the highest on record. Production of oilseeds may exceed last year's level by about five lakh tonnes. Sugarcane production is estimated to be around the record level of last year. In brief the crop year 1977-78 was the best on record and the crop year 1978-79 is likely to be still better Thus, the accent on sound public policies we have introduced is bound to pay good dividends in the coming years.

However, I would hasten to caution that there is no cause for euophoria and absolutely none for complacency We cannot relax our efforts to make agriculture an important instrument of rural and agrarian prosperity.

Some of my hon friends were mentioning about pulses. They are worried about pulses. Last year they were worried about vegetables also. This time they did not talk of vegetables because vegetables were in good production and prices have come down. Some hon. Members mentioned inter crop imbalances; food grains production had increased while the production of pulses and oilseeds has not increased considerably. We are aware of this problem and special efforts are being made to increase the production of pulses. Research efforts for evolving high yielding varieties had been intensified. Production of breeder, foundation and certified seeds of good quality is being promoted The Central Government gives sibsidy for production of certified seeds at the rate of Rs. 150 per quintal and on breeders' seeds at the rate of Rs. 300 per quintal for gram, arhar and lentil and Rs. 500 per quintal for moong, urad and cow peas. Measures such as the application of phosphatic fertilisers, rhizobial culture, plant protection measures, intensive training of farmers in improved technology of production of pulses, cultivation of moong and urad in rice fallows and inter-cropping of pulses are being undertaken for increasing their output Cultivation of short duration zaid crop of moong in Uttar Pradesh gave encouraging results last year. On the basis of that experience, the cultivation of zaid crop of moong is being extended over an area of about 3.5 lakh hectares in the current year. In Orissa and in other States also this is being taken up

Then there was a mention that the support price of pulses should be raised I may mention that the minimum price of gram was Rs. 95.00 per quintal. The hon. Member may be knowing that in 1977-78 the support price of gram was only Rs. 95.00. But it was raised to Rs. 125.00 last year and the price has again been raised now to Rs. 140 per quintal for a current year's crop. Further, for the first time the support price of Arhar and Moong was fixed at Rs. 155 and 165 respectively last year. Special extensive drive will be launched to promote cultivation of pulses in all the irrigated areas.

Similarly, regarding oilseeds also special efforts have been made for production of good seeds and support price also has been raised for groundnut from Rs. 140 per quintal in 1976-77 to Rs. 175 per quintal in 1978-79. During the same period the support price of Sunflower seed has been raised from Rs. 150 to Rs. 165. In case of Soyabean which is now taking good roots in the country, the minimum support price was stepped up

from Rs. 145 per quintal in 1977-78 to Rs. 175 per quintal in 1978-79. This year's production of Soyabean has been very good particularly in Madhya Pradesh and we had initiated purchase on support price and we have purchased about 70,000 tonnes of Soyabean for the first time.

One of the reasons for the low yields of these crops has been their cultivation mostly under unirrigated conditions. We are now planning to introduce suitable pulses and oil seeds crops in all the irrigated farming systems This together with the price support policy already introduced should help us to step up production of pulses and oil seeds considerably

I must congratulate scientists for developing a wide range of crop varieties possessing resistance to major pests and diseases Recently the Central Committee on Release of Varieties has approved the release of 17 new wheat strains suitable for cultivation in different parts of the country. Similarly, our rice scientists have developed a wide range of new varieties some of which do well in conditions of water stagnation.

I must inform the hon. members that the weather both in 1977-78 and in 1978-79 was very favourable for incidence of diseases like wheat rusts. However, our crops were not affected largely because of disease control strategy developed by our scientists I am also happy to report that the seed of wheat variety we supplied to Pakistan last year has done very well. Some of the leading newspapers in Pakistan have reported that the varieties like HD-2009, WL 711 and Sonalika supplied by India have been free from diseases and are expected to give good yields.

The Indian Council of Agricultural Research which is completing 50 years of useful service to the farming community this year has chosen 'Lab. to Land' as its major activity during the Golden Jubilee Year. This programme envisages a massive effort in the area of transfer of the latest scientific skills and knowhow from the laboratories of Agricultural Universities and Institutes to the fields of marginal and small farmers. The 'Lab. to Land' programme will be closely integrated with our programme for intensive rural development so that we are able to make speedy progress in bridging the wide gap now existing between potential and actual farm yields.

Hon. members are aware of the various steps we have taken to build up grain reserves and to enhance our storage capacity. My colleague, Shri Bhanu Pratap Singh has dealt with that aspect and I need not mention anything more. But Shri Jaiswal today said that we are not creating enough storage capacity for the foodgrains and that is why a lot of foodgrains get wasted. He is correct in saying that enough storage capacity, as was required in the country, was not created. Now there is an effort from many sides to bridge that gap and to have more and more covered storage capacity. I may inform hon. members that within the last two years we have got about 40 lakh tonnes of new covered storage capacity through various methods. Shri Bhanu Pratap Singh has mentioned that we have a plan for having about 2000 rural storages with a capacity of 200 to 250 tonnes, which will be very useful These block level storage structures will be designed not only to store grains but also inputs like seeds, fertilisers and pesticides. In addition, a cold storage wing for storing perishable commodities will be added to the block level storage system wherever necessary. We did not have community drying facilities so far. Community drying facilities will be provided as a part of the storage complex. This is particularly important since there are several reports now which indicate that liver diseases occur due to the infection of grains by fungi leading to the formation of toxins in the grains. Such infection occurs only in grains containing a high moisture content, as a result of

[Shri Surjit Singh Barnala]

inadequate drying. That is why we are trying to provide drying facilities also.

Regarding ecological security also, several members have made mention. Without adequate ecological security, we will not be able to sustain agricultural advance continuously. That is very important. There were complaints of deforestation. I myself have those complaints. I have been mentioning to my colleagues, that deforestation takes place on every pretext Whenever there is to be a dan. or reservoir, deforestation takes place. When those people have to be rehabilitated, they are rehabilitated on forest lands. So, again forest lands are denuded. Whenever a road is to be constructed, particularly in mountainous areas where there are forests, that is also done at the cost of the forests. Whenever any project is introduced in any State, it is at the cost of forest land. I saw in some areas where high tension electricity wiring was to be done, this was done at the cost of forest area. The forest was cut wherever the lines had to be taken. So, everything is done at the cost of the forests. I am myself quite worried about that. We are adopting a strategy whereby we can maintain the forest wealth that we have now and also we could increase the forest wealth in a suitable manner.

AN HON. MEMBER: Is there any time-bound programme for that?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We are trying to have a time-bound programme also.

I shall now mention the major factors which have contributed to increase in agricultural production. One is, continuous flow of improved technology. We are very satisfied with this. In fact, we are trying to improve this also. Our agriculture scientists are some of the best in the world and this has been acknowledged by other top-most scientists in the world. I had opportunities of talking to many of them and they have praised our agriculture scientists very much. Then, extension of irrigation facilities, substantial step-up of fertiliser consumption, extension of areas under high-yielding varieties, arrangements for quick and effective transfer of new technology to farmers, larger and easier flow of agricultural credit to farmers, remunerative price and improved marketing policies. These are the main factors.

15 hrs.

Regarding irrigation, my hon friend, Mr. Bhanu Pratap Singh, had already mentioned that last year, there was a record increase of irrigation facility in this country. I may inform the hon. Members that during the year 1979-80, we are hoping to achieve a bigger goal. We are aiming at 3 2 million hectares during the next year as compared to 2 8 million hectares achieved this year. So, there will be a significant improvement and we hope that within the next five years the target of 17 million hectares of irrigation will be achieved.

Among the irrigation programmes, special emphasis has been laid on minor irrigation schemes which are quick maturing, less expensive and generate large employment. The measures taken in this regard include increase in investment on minor irrigation schemes, particularly from institutional resources, identifying and removing bottlenecks and achieving closer coordination with the rural electrification programme A programme for installation of 3500 public tubewells, 2.25 lakh private tubewells. 2.75 lakh dug wells and 3.5 lakh electric pumpsets has been taken up during 1978-79, and we hope that it will be achieved.

The major and medium irrigation works take time to be completed. Our irrigation strategy provides for a high priority to expeditious completion of a large number of irrigation projects which have been under implementa-

tion for the last several years, so that they start yielding benefits in terms of more irrigation.

Drainage which had been neglected in the past is now receiving special attention. We are carefully examining this aspect and necessary provision is being made under all new projects for adequate drainage facilities as a part of the modernisation programme. At the instance of the Government of India some of the State Governments have already set up expert groups to make a thorough study of the problem and formulate a comprehensive programme for modernisation of irrigation projects.

The command area development programme which aims at optimising the utilisation of the available irrigation potential has made further headway. 38 command area development authorities have been set up in the States. The programme now covers 60 irrigation projects having an ultimate irrigation potential of about 13 million hectares. The programme under the current Five Year Plan envisages construction of field channels in 10 lakh hectares and completion of on-farm development works over an area of 20 lakh hectares.

Regarding flood control which is also very important, last year's severe floods raised many issues which we have tried to solve. A Working Group was constituted to go into this matter. They have prepared an action plan which provides for an integrated approach to engineering works, soil conservation, afforestation and water-shed management. It will involve an investment of Rs. 1000 crores on engineering works and Rs. 700 crores on soil conservation, afforestation and water-shed management within the next five, six years.

Regarding fertilisers, its consumption has registered significant advances in recent years. We are not only trying to take care of in organic fertiliser but we are taking care of compost fertiliser also. A comprehensive programme for the development of local manurial resources is also being implemented in the country. This includes production of rural and urban compost, green manuring, sewage and sullage utilisation, setting up of mechanical compost plants and installation of gobar gas plants. A low cost bio-gas plant has been developed and the technical feasibility of installing such plants on a large scale is being explored.

The high yielding varieties programme was taken to more and more areas. During 1977-78 the programme covered 38 million hectares which is likely to be extended by another 4 million hectares during the year 1978-79. There will be further increase during the coming year.

Special extension effort has also been made so that the technology of improved irrigation, improved agriculture, improved seed can be taken from the laboratories of universities to the farmer's field. This is also being done.

I would like to make a special mention of the "Training and Visits System" of agricultural extension, which has already been taken up in 9 States and is being extended to other States as well. This has proved very successful.

Then I come to agricultural credit, which is very important and which was mentioned by several hon. Members. We are trying to improve the availability of agricultural credit. The quantum of credit extended to farmers rose from Rs. 2,000 crores in 1976-77 to Rs. 2,400 crores in 1977-78 and is likely to go up to Rs. 2,750 crores by the end of June, 1979. The commercial banks increased the number of borrowers from 32.74 lakhs in 1976-77 to 52.74 lakhs in 1977-78. It is expected to go up to 63 lakhs in 1978-79, which is almost doubling, and it is a very good sign.

There are many allied sectors of agriculture like animal husbandry, dairy development, fisheries and forestry which we are taking care of. For want of time, I will not be able to deal with them in detail. In the animal husbandry sector, the programmes for increasing the production of protective foods of animal origin, *viz.*, milk, eggs etc. have received special emphasis. The Special Livestock Production Programme for Cross-bred heifers and setting up poultry, piggery and sheep production units for the benefit of small and marginal farmers and agricultural labourers have been extended to more areas and 268 projects are now in operation in 183 districts of the country. It is estimated that each project will benefit at least 5,000 families of small and marginal farmers and agricultural labourers under the Cross-bred Calf Rearing Programme, 3,000 families under the Poultry and sheep Production Programme and 500 families under the Piggery Development.

A massive Cross Breeding Programme and selective breeding has resulted in increasing the milk production. My hon. friend was saying that it has never been mentioned as to what is the milk production in the country and how it is affecting the availability. The milk production rose from 23.2 million tonnes in 1973-74 to 27.5 million tonnes in 1977-78. The *per capita* availability of milk per day has increased from 111 grammes in 1973-74 to 120 grammes in 1977-78. We know this is not enough, this is not sufficient. That is why we want to increase this production further under this programme. Similarly, the production of eggs has increased from 7,700 million to 11,000 million by the end of 1978.

The availability of livestock and poultry feed at reasonable prices has been assured. This has been achieved mainly through rational export policy of feed nutrients like groundnut extraction and monitoring of demand and supply of nutrients like rice polish, wheat bran etc.

Coming to dairy development, I would like to make a special mention of the Operation Flood II Programme, which represents a massive effort for increasing the production of milk in the country. This is a fairly big programme with an investment of Rs. 485 crores over a seven-year period. It is expected to benefit 10 million farm families and encompass a national milch herd of 15 million productive cross-bred cows and upgrade buffaloes.

Coming to fisheries, high priority is being accorded to the development of fisheries for providing nutritious food as well as for generating employment. It is proposed to increase fish production to 22 lakhs tonnes from the Marine Sector and 12 lakh tonnes from the Inland Sector during the five year period 1978—83.

The declaration of 200 miles of exclusive economic zone from the coastline has placed at our disposal vast resources which are proposed to be exploited through massive efforts of deep sea fishing. As against 52 vessels at the beginning of last year, by the end of this year the number will increase to 130.

15.10 hrs.

[**Shrimati Parvathi Krishnan** *in the Chair*].

In addition, 1202 additional small mechanised boats were introduced. In all, about 15,432 small mechanised boats are expected to be in operation by the end of 1978-79. To avoid unhealthy competition between the country boats, mechanised boats and deep see trawlers, our endeavour would be to improve the harvest from the sea by stimulating on an equitable basis, the growth of country boats, mechanised boats and deep sea fishing trawlers.

To promote inland fisheries, 50 Fish Farmers Development Agencies have been set up for utilisation of tanks and ponds covering an area of 1.6 million hectares for intensive fish culture.

The Central Sector Scheme of brackish water fish culture is also being implemented in maritime States mainly for utilisation of brackish water area for fish culture available in the country to the extent of 1.42 million hectares.

Regarding afforestation, Madam, the Government has accorded high priority to the development of forest resources with a view to preventing recurrence of floods, controlling soil erosion and maintaining ecological balance. The programme for the development of social forestry, raising of fast-growing species and other valuable species of economic and industrial importance, adoption of better extraction techniques and improvement of forest communications, were intensified during the year. There have been good results also. "For example, in social forestry, the investment in 1976-77 was Rs. 1.63 crores only. In 1977-78 the investment was Rs. 7.37 crores and in 1978-79 the investment has been Rs. 9.20 crores in social forestry and the results obtained are also good. In 1977-78 the plantation of wastelands was 17,600 hectares and mixed and degraded lands, 43,600 hectares and 5,400 of running kilometres, that is, alongside roads and canals etc. In 1978-79 much more improvement has been made that, is for plantation of wastelands, the area is 36,630 hectares, for mixed plantation 83,700 hectares, and regarding afforestation of degraded forests, canal banks, roads etc, 37000 running kilometres. This was an achievement which is, to my mind, a good achievement."

It is estimated that a total area of 3.4 million hectares would be covered under man-made forestry through State as well as Centrally sponsored schemes.

The draft of the Revised National Forest Policy is under the consideration of the Government of India and we are taking into consideration many points. One is that diversion of forestry lands to non-forestry uses should be allowed only through the approval of State Legislatures. Secondly, the limit of forest area in the hill regions of the country should be at least 60 per cent of the total areas of the region and thirdly, all projects which involve deforestation should be examined from environmental and ecological angles by the Planning Commission and National Committee on Environmental Planning and Coordination, Government of India, and no project should be taken up unless it has been cleared by these agencies So, that is the method by which we try to impose some restrictions on the State Governments for achieving this object.

Regarding land reforms, Madam, a lot has been said by many hon. Members that nothing is being done. I may say and reiterate once again that the Government is committed to the speedy implementation of land reforms. Just now an hon. Member was saying: "We should be told what has been achieved during these two years." After the assumption of charge by the Janata Government, I must say that since March 1977, 5 lakhs acres of land have been distributed to more than 3.03 lakhs beneficiaries during these less than 2 years. So, I may say that we are committed to speedy implementation of land reforms and I would say that this record is better than the previous record.

An important step has also been taken in this direction by setting up a committee under the chairmanship of Prof. Raj Krishna, Member, Planning Commission, to review the progress of land reforms, and they have submitted their first report One of the recommendations of that report has also been adopted.

I may mention here that the Government of India has decided to amend the Ninth Schedule of the Constitution so as to cover all land reform laws which have not been so far included therein or which may

be enacted by the States in future, with a view to protect them from avoidable delays through vexatious challenges in courts of law, because that is the main problem. A lot of court cases are pending. Though the State Governments have taken possession of some land, courts issue injunction and stay orders. That is why the distribution of land is stayed, and State Governments face difficulty. So, we are bringing all these laws under the Ninth Schedule of the Constitution.

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): What about the Kerala Bill?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Would it be proper for me to mention it here?

Mention was made here by many Members of the fixation of prices, and it was said that the prices which have been fixed for wheat, rice etc., are not remunerative. Many types of objections were raised. I may mention for the information of the hon. Members—I have taken the data for the last 10 years—that in 1968-69 the price of standard paddy was Rs. 52.50 per quintal in Punjab and Haryana, and that of standard wheat was Rs. 76. Paddy prices were again revised in 1972-73 to Rs. 53. Till then, for five years it remained almost the same. From 1968-69 to 1973-74, the price of wheat remained at Rs. 76. Nobody changed the price. But now some Members want a change every year. Then, after the hike in world prices, because fertiliser prices went up, the urea price to Rs. 2000 a tonne, the prices were revised. In 1974-75 the prices of paddy was raised to Rs. 76 and the price of wheat was raised to Rs. 105 and thereafter it remained like that for three years again. Till 1976-77, till the end of the emergency, the prices remained the same but in 1977-78 we raised paddy price from Rs. 76 to Rs. 79 and wheat price from Rs. 105 to Rs. 110. Again, last year, in 1978-79, the paddy price was increased by Rs. 8 to Rs. 7 and wheat price by Rs. 2.50 to Rs. 112.50. Now again it has been raised by Rs. 2.50 and now the wheat price is Rs. 115.

SHRI B. K. NAIR: Why no revision for paddy?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It is coming later.

This is the situation. Prices remained constant for many years, at Rs. 76 for six years and at Rs. 105 for three years, when, I remember, we used to agitate that they should be raised because the cost of inputs had gone up, but it was not raised for three years continuously. It was raised only in 1977-78.

Some hon. Members have also mentioned that prices of wheat have been raised more steeply than that of paddy. This also is not correct. I may mention that between 1969-70 and 1978-79, in the marketing season the procurement prices of wheat have been raised from Rs. 76 to Rs. 115, i.e., by 50 per cent. As against this, the increase in the procurement price of paddy has been about 65 per cent so that the contention is not correct that wheat prices have been raised more than paddy prices. The prices of almost all the other commodities, as I have mentioned in my reply, have been raised from time to time. So, what is now required and what is agitating the mind of the hon. members is marketing. We are producing some of the items, particularly these perishable items, for which we do not have enough market, we do not have processing facilities, storage facilities and that is facilities, storage facilities and that is why we have this difficulty in the case of potatoes and in the case of vegetables also this year. But we are adopting certain policies now for storage and for export also and we are trying to evolve some strategy which will be ultimately beneficial to those farmers who are producing these items like potatoes and onions. These are two items on the export of which we had imposed a ban at a time when their prices in the country

had gone very high. Then, when the production was good, that ban was removed and we have brought them under OGL also. But still, because there has not been enough market, there has not been enough export. We have been able to export only 23,000 tonnes of potatoes so far. Much more should have been exported because NAFED has purchased a lot more, but they have not been able to export it. For exporting certain items, we have to remain in the export market for a long time and for that we are evolving a strategy that we should produce these items for export purposes in a larger quantity so that they can be utilised for export only. Similarly for vegetables also, fresh vegetable market is close at hand in the Middle East. We are in a position to export some vegetables. It was not possible last year because the prices of vegetables had gone high here as a result of the shortage of vegetables. But this year, the prices of vegetables have come down considerably. Now we are thinking of exporting green vegetables to the neighbouring countries, and to remain in the market for a long time. For that we are asking the State Governments to create some infrastructure through which they can have production of vegetables, particularly the special type of vegetables on a larger scale for a longer time. Some Governments, like Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab, are interested in producing more vegetables so that a part of that can be exported.

MR. CHAIRMAN: What are the special type of vegetables?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Lady fingers and brinjals are the two types of vegetables which are required in the Middle East. Punjab Government have recently told us that they are in a position to supply twenty tonnes each of both these vegetables every day for export purposes and that they can send one special plane every day. Similarly Maharashtra is willing to produce ten tonnes each of these two vegetables.

We are thinking of exporting vegetables like this. For potatoes we need more cold storage facility in the country. During the last five years, the production of potato has nearly double but the cold storage capacity has increased by about 50 per cent only. That is not enough to meet our requirements. About 80 per cent or more of the cold storage capacity is essential to be used for storage of potatoes...

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : कोल्ड स्टोरेज की जो तादाद आपने दी ही है कि 50 परसेंट बढ़ी है, यह ज्यादा बता दी आपने।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 50 परसेंट बढ़ी है थोड़े दिनों में।

(व्यवधान)

मैं बात करता हूं। पहले हम कोशिश यह कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाया जाये, जैसे शुगर के बारे में मैंने कहा था डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना है। अपनी तो आबादी इतनी बड़ी है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हो सकता है। अब आलू की पैदावार 90, 91 लाख टन के दर्मियान है। लेकिन इतनी आबादी के लिये काफ़ी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आलू तो सड़ गया।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सड़ तो इस लिये गया कि लोग खाने के आदी नहीं हुए हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : परचेजिंग कैपेसिटी है। आलू तो मिल रहा है 40 पैसे का एक किलो और चावल व गेहूं मिल रहा है सवा रुपये और डेढ़ रुपये का किलो। हरेक आदमी गरीब से गरीब भी चावल और गेहूं खरीदना चाहेगा लेकिन 40, 50 पैसे किलो

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

का आलू नहीं खरीदेगा हालांकि उसकी फूड वैल्यू ज्यादा है ।

मुझे पता है, आप को शायद पता नहीं हो कि सरदार इकबाल सिंह आलू बहुत तादाद में पैदा करते है और उनको पटैटो किंग कहा जाता है । उनके पास जमीन ज्यादा नहीं है, जमीन की वजह से पटैटो ज्यादा नहीं होता है He is the topmost producer of potato in the country. So, he knows all this. इसलिये उनको कोल्ड-स्टोरेज का काफी पता है, कहां कैसे दिक्कत आई है यह भी पता है । आलू रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा ।

MR. CHAIRMAN: When you said, "potato king", I thought, he consumes the largest number of potatoes!

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Not that. But I have a complaint on that score against him because he does not consume much sugar nor potato. I would request the hon. Members that, in fact, we should encourage the potato eating habit. Potato should be taken not as a vegetable—ऐसा नहीं कि सालन की तरह चावल के साथ या रोटी के साथ थोड़ा खा लें । Potato eating should be made a food habit.

Now, we have started producing potato in all parts of the country. Two days back, I was in Calcutta. They are producing so much potato. 21 lakh tonnes of potato have been produced in West Bengal alone. Earlier, potato from U.P. and other parts used to go to West Bengal and Assam. They are now producing potato for themselves.

श्री बसन्तराव साठे : आप अपने मास मीडिया का इस्तेमाल करिये ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मास मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिये, मास मीडिया का सबसे बड़ा काम तो हमारे मेम्बर्स कर सकते हैं वह 50, 60 हजार की गैदरिंग में जाकर जब बोलते है तो उनको लोगों से कहना चाहिये कि आलू खाना अच्छा है । तो थोड़ा आलू का प्रचार होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : चीनी के बारे में . . .

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : चीनी तो कुछ समय के बाद आपको मिलेगी नहीं । मुझे तो यह मालूम हुआ है कि जो एक चम्मच चीनी खाता था, वह अब दो चम्मच खाने लगा है । पहले चीनी गांव मे जाती नही थी, अब जाने लगी है इसलिये 37 के बजाय 60 लाख टन चीनी की कंजम्पशन होने लगी है । पहले यही था कि उनके पास गांव में पहुंचती नही थी, शहर के लोग ही खा जाते थे, राशन में भी ले ली और वैसे भी ले ली । किसी न किसी तरह से शहर में ही इस्तेमाल हो जाती थी इसलिये दिक्कत रहती थी । अब गांव में जाने लगी है, गरीबों के पास पहुंची है । अभी तक लोग समझते थे कि शायद यह अमीरों के लिये ही बनी है हमें तो गुड़ ही खाने के लिये मिलता है । अब गांव मे लोगों ने खाना शुरू कर दिया है । इसीलिये चीनी की कंजम्पशन बढी है । कंजम्पशन हर बात की बढ़नी चाहिये ।

अनाज के बारे में कहा गया कि हमारे पास बहुत हो गया, लोग कहते हैं कि सड़ गया है । सड़ने की बात नहीं है । अनाज आम तौर पर कहीं रखा जायेगा, कोई भी रखेगा, आप घर में भी रखेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत अनाज घर में रखता हूं तो जानता हूं कि जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है । कभी सीलन में नुकसान हो जाता है, चूहे खा जाते हैं, काबू नहीं कर सकते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है । देश में बहुत से भंडार ऐसे थे जिनके ऊपर छत नहीं थी तो उन पर

पोलीथीन कैप्स रखनी पड़ीं । साइक्लोन आ य, उससे वह नीचे गिर ग , इसी तरह आंधी, व रिश आई तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान होता रहा है। कई जगह लीकेज शुरु हो जाता है, अपने घरों में भी कोशिश करने के बा जूद लीकेज हो जाता है । इसलिये हमारा लास इतना नहीं है, जितना कि कहा जाता है कि बहुत सड़ गया । जहा इतनी बड़ी मात्रा मे अनाज रहता है, 15 मिलियन टन, 17 मिलियन टन तो कही कही उसमें थोड़ा बहुत लास होता रहता है लेकिन इससे फायदा यह हुआ है कि देश के किसी भी हिस्से मे आज ऐसी दिक्कत नही है कि हमारे यहा अनाज नही मिल रहा है या ठीक दाम पर नही मिल रहा है । म रे देश मे एक ह। दाम प इश्यू प्राइस पर अनाज मिल रहा है, और रिमोटेस्ट पार्ट मे भी मिल रहा है और यह हैल्दी साइन है ।

केरल मे जब मैं गया तो मैंने क ा कि आपको थोड़ा-बहुत कानून मे मौडिफिकेशन करना चाहिये । उन्होने कानून बना रखा है, जिसके नीचे —

"A particular land which has come under paddy cultivation has to remain under paddy cultivation' So, I told the State Government that they could now modify the law because enough rice is available in the country. It could move out from Andhra' Pradesh; it could move out from Tamil Nadu. I told them, "Whatever quality of rice you need, that will be made available. Why not use this land for some better purpose?"

That is why I had suggested. In respect of the other States also, I have been suggesting that we should adopt only those agricultural methods and take to those agricultural crops by which the farmer gets the maximum production and the maximum yield.

I must conclude now. I have taken a long time. In the end, I thank the Indian farmers who have been helpful in improving the agricultural production in the country, the agricultural scientists and also the weather God who,, I would say, has been quite helpful though not in all the areas equally nonetheless has been quite helpful—in increasing food production. I am also thankful to all the hon Members who have very actively participated in this debate. I would now request that these Demands for Grants may please be voted.

SOME HON. MEMBERS: *rose*—

MR. CHAIRMAN One at a time. Mr B K Nair Shri B. K. Nair

SHRI B K. NAIR (Mavelikara): I had asked a specific question about Kerala regarding institution of a welfare fund for fishermen by raising a cess on the exports No answer has been given to that. I had also requested about the supply of suitable quality of rice to Kerala because much of it is being rejected; it is beyond the purchasing power of the people and it is held up in the godowns.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): The Agriculture Minister was advocating about parity price. What happened to it? I wanted remunerative price for the agriculturists and a reasonable price for the poor consumers.

SHRI A. K ROY (Dhanbad): The Minister has informed us that five lakh acres of land have been distributed. I think, this amount of land has been distributed on the basis of the old laws. I want to know whether the Central Government is contemplating to give new guidelines to the States to have new land laws, so that more land can be extratced from the land-owning class?

श्री अनन्त राम जायसवाल : राज्य नया गेहू खरीदने की तैयारी कर रहे है ।.राज्य अनुभव कर रहे हैं कि कई जगह बोरे नही हैं ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है ? इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मंत्री महोदय ने कहा है कि पिछले दो सालों में 3.5 लाख परिवारों को 5 लाख एकड़ भूमि बांटी गई है। क्या वह इससे संतुष्ट है ? इस तरह लगभग डेढ़ एकड़ भूमि एक आदमी को मिली है। इस देश मे डेढ़ करोड़ परिवार भूमिहीन है। केवल 5 लाख परिवारों को भूमि देना समुद्र में जल-कण के बराबर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश मे भूमिहीन परिवारों को जमीन दिलवाने के लिए क्या वह राज्य सरकारों को भूमि-सुधार कानूनों में इस प्रकार से संशोधन करने का निर्देश देंगे ताकि हजारों एकड़ जमीन का स्वामित्व रखने वाले किसानों से भूमि सीमा से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि खेती के लिए दी जा सके।

SHRI IQBAL SINGH DHILLON (Jullundur): There have been many announcements by the Government that the procurement prices of pulses and oilseeds have been raised and Government is proud of that. But the market prices of pulses and oilseeds are much more than the announced procurement prices. Therefore, how can this help the production and the farmers?

श्री चंदन सिंह (कैराना) : सभी संसद् सदस्यों ने यह जिक्र किया कि क्राप की और कैटल की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो क्या माननीय मंत्री जी इस चीज के लिए भी कुछ आश्वासन देंगे ? जैसे गेहूं है या तिलहन है, ओला वृष्टि से यह फसल बरबाद हो जाती है तो क्या उसके लिए क्राप इंश्योरेंस करने का आश्वासन देंगे और कैटल का भी इंश्योरेंस करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अविराम अंगल (मुरैना) : माननीय मंत्री जी से यह कहा है कि भूमि कटाव रोकने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं चम्बल डिवीजन के मुरैना क्षेत्र से चुनकर आता हूं। चम्बल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीन स्टेटस से होकर जाती है और उसके द्वारा हर साल करीब 5 लाख एकड़ काबिले काश्त जमीन कट जाती है और बहुत सी जमीन बीहड़ बन जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस कटाव को रोकने के लिए फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत कोई योजना बनाएंगे और जो बीहड़ जमीन है उसका समतलीकरण करेंगे ?

श्री राघवजी (विदिशा) : खाद्यान्नों की जो सपोर्ट प्राइस घोषित होती है वह आमतौर पर फसल के मार्केट मे आने के बाद घोषित होती है, क्या माननीय मंत्री जी इस को घोषणा फसल बोने के पूर्व कराने की व्यवस्था करेंगे और ओला वृष्टि से जो नुकसान होता है उसे रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक उपाय खोजने की कोशिश करेंगे ?

MR. CHAIRMAN. I am calling those who, in the beginning raised their hands. But you cannot get ideas from other people's questions. That is not allowed. Mr. Bhagat Ram.

श्री भगत राम (फिल्लौर) : खेती में मशीनरी के इस्तेमाल से हमारे देश में जो हजारों खेत मजदूर हैं उनके हाथ कट जाते है और वे ऐक्सीडेंट से मर जाते हैं तो उनको कम्पेन्सेशन देने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे है और दूसरा मेरा वक्तव्य है .....

MR. CHAIRMAN: Only one question is allowed. I have called Mr. Kodiyan. You will please resume your seat.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): Madam, Chairman, the hon. Minister has not replied to one important

question that was raised during the discussion regarding the recent increase in the price of sugar due to the manipulation of the sugar magnates

MR. CHAIRMAN: What is that question? You put it again.

SHRI P. K. KODIYAN: The price of sugar which was Rs. 2.60 has gone up to Rs. 3.20. What action does he propose to take in this regard?

SHRI VAYALAR RAVI (Chilayinkil) They have taken money.

MR CHAIRMAN: Mr. Rajiv please allow him to put the question.

SHRI P. K. KODIYAN: What measures does the Government propose to take against the mill magnates both the private and cooperative sugar mill magnates, who had manipulated the price increase by not releasing adequate quantity of sugar to the market.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Madam, I could not follow Mr. Nair's question Can you repeat that question?

MR. CHAIRMAN: You want Mr. Nair to repeat his question. Mr. Nair, you will please repeat your question. That does not mean that everybody else can repeat his question.

SHRI B. K. NAIR: My question is about the institution of a welfare fund for the sake of fishermen based on a sort of a cess to be imposed on the exports which run to Rs. 180 crores a year.

MR CHAIRMAN: Mr. Nair, do not take this as an excuse for your speech.

SHRI B. K. NAIR: I have suggested that a case may be imposed on the exports of marine products now valued at over Rs. 180 crores and that the fund so raised may be utilised for creating a welfare fund for fishermen and for insuring them against accidents and death while at sea. I have also peaded for ensuring supply of acceptable quality rice to Kerala.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I have no proposal so far regarding imposition of cess on exports and then utilise that money for the betterment of fishermen. There are other schemes by which the fishermen can be benefited.

Madam, there are many questions raised and I shall try to answer all of them.

MR. CHAIRMAN: And answer them as briefly as possible.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I shall answer them as briefly and as quickly as possible.

There was a mention regarding the Agricultural Prices Commission. The question was whether we would try to change the terms of reference of the Agricultural Prices Commission. I have already mentioned in my speech that that is under active consideration. Regarding the land reforms also a mention was made by Shri Shastri ji saying that now we have 1½ crores of landless families:

उनको जमीन कब देंगे ? अब मेरे हाथ में कोई जादू तो है नहीं कि मैं खींच कर जमीन को बढ़ा दूं और उसको थोड़ा-थोड़ा करके बांट दूं । यह तो जो जमीन अबेलेबल होती है उस को बांटती है । उसमें से मैंने बता दिया है .... (व्यवधान)

MR CHAIRMAN: Will you please resume your seat? You speak from your knowledge. The Minister speaks from his knowledge. You cannot go on shouting.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो कानून बने हैं सभी प्रान्तों में, उनके नीचे जितनी जमीन सीलिंग हो रही है, जितनी सरप्लस

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

जमीन बनती जा रही है उसको बांटते चले जा रहे है । इसमे किसी प्रान्त मे आधा एकड़ जमीन दी गई है, कही एक एकड़ दी गई है और कही पर डेढ एकड़ दी गई है । कही पर यह ठीक हो सकती है और कही पर गलत हो सकती है । किसी प्रान्त मे एक एकड जमीन बहुत होती है और कही पर कुछ भी नही होती है । मै यह नही कहता कि बहुत जमीन दे दी गई है लेकिन इससे ज्यादा जमीन दी नही जा सकती थी (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has referring to Shastriji Not to you.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दूसरी बात यह कही गई है कि पलसेज की मार्केट प्राइस ज्यादा है लेकिन सपोर्ट प्राइस थोडी नियत की गई है । तो सपोर्ट प्राइस एक रीजनेबल प्राइस मुकर्रर की जाती है जिसके नीचे अगर प्राइसेज जाती है तो सरकार को खरीदना पडेगा । अगर मार्केट मे किसान को सपोर्ट प्राइस से ज्यादा दाम मिलते है तो बहुत अच्छी बात है । (व्यवधान) जैसे गेहू के लिए 115 रुपए क्वींटल सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है (व्यवधान)

श्री उपसेन : एग्रीकल्चर की डिमान्ड्स पर हम लोगो को बोलने का मौका ही नही दिया गया । हमको बोलने का हक है जनता ने इसीलिए यहां पर हमको भेजा है । हम तो सवाल करेंगे ।**

MR CHAIRMAN: Such remarks against the chair, will not go on record; Don't make any remarks against the Chair. According to the list submitted by the Party. Members are called.

SHRI VAYALAR RAVI: Mr. Ugra Sen should not attack the lady in the Chair.

**Not recorded.

MR. CHAIRMAN: I don't think it bothers him whether it is a lady or otherwise. He indulges in such threats, that is part of his existence in life!

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दिल्लो साहब ने कहा कि पलसेज की प्राइमेज मार्केट मे ज्यादा है लेकिन सरकार ने सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर की है फिर इसमे क्या क्रेडिट है । तो हम इसका क्रेडिट नही ले रहे है । अगर मार्केट मे प्राइमेज ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर सपोर्ट प्राइस से नीचे मार्केट मे प्राइमेज जाती है तो सरकार को खरीदना पडेगा । जैसे गेहू के लिए सपोर्ट प्राइस 115 रुपए है, अगर बाजार मे 120 रुपए मिलते है तो किसान वहा पर बेचे, कोई कोअर्सन प्रोक्योरमेट नही है । जितने पर भी बिकता है, बेचे लेकिन अगर मन्डी मे 115 पर बेचने के लिए आयेंगे तो सरकार खरीदेगी । इसलिए मै ने कहा कि सपोर्ट प्राइस इसीलिए मुकर्रर की जाती है जिस पर खरीदना ही पडेगा ।

माननीय सदस्य ने चम्बल के कटाव का जिक्र किया और कहा कि वह उनकी कास्टीटएन्सी है । मुझे पता नही था, अगर पता होता तो उसका जिक्र कर देता । मैने फलड अफेक्टेड एरियाज का जिक्र किया था लेकिन यह रिक्लेमेशन की बात है । चम्बल यहा जहा से होकर जाती है, हम कोशिश मे है कि जहां रिक्लेमेशन हो सकता है वहां कर लिया जाये लेकिन कही कही पर चम्बल का कटाव बहुत गहरा है जहा पर रिक्लेम करना मुमकिन नही है । इसलिए जहा पर कटाव बहुत गहरा है वहां पर जगल लगा दिए जायें और जहा पर आसानी से थोडे पैसे मे रिक्लेमेशन किया जा सकता है उसको रिक्लेम करके काबले काश्त बना दिया जाए । (व्यवधान)

Regarding crop insurance and cattle insurance, Madam, I did not say anything. I forgot to say anything Now, regarding Crop Insurance, I would like to tell the hon. Members that the General Insurance Corpora-

tion of India has finalised a pilot Crop Insurance Scheme based on area approach. The scheme will be for homogeneous agro-climatic blocks with common premia rates and indemnity. Cover would be provided against all climatic risks as also against pests and plant diseases The State Government will have to participate as co-insurer sharing claim as well as premium to the extent of 25 per cent. This scheme involves collection of substantial data on crop cutting experiments and in-depth study for deriving indemnity limits as well as premia payable. Premium indemnity tables have already been prepared for 12 States and one Union Territory. The General Insurance Corporation has however introduced a Crop Insurance Scheme for H-4 cotton is certain parts of the State of Maharashtra and Gujarat against all climatic risks (except drought) as also against pests and plant diseases.

Now, in regard to Cattle Insurance I would like to tell you that the subsidiaries of the General Insurance Corporation of India have been conducting cattle insurance business since 1974 for the indigenous, cross-bred and exotic (imported) milch cattle. The sum assured varies from 80-100 per cent of the market value or the bank advance. The insurance covers death due to accident or disease subject to some specific exclusions. The scheme is already extended all over the country.

A special concessional rate of premium is offered to the milch cattle and stud-bulls of India and cross bred variety in the age group of 3-8 years purchased by the beneficiaries (small and marginal farmers) under the SFDA/DPAP scheme since 1st April 1977. The insurance is provided against death due to accident or disease subject to certain exclusions. A scheme for providing insurance to cover cross-bred heifers/calves in the special project areas has been finalised.

एक अनरेबिल मेम्बर ने जिक्र किया कि काम करते हुए थ्रेशर से हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है—उस का भी बीमा होना चाहिये । मैं उन को बताना चाहता हूं कि इसके लिये भी एक स्कीम चलाई है, जिसको 'जनता इंशोरेंस" कहते है । इस के अन्दर 12 रुपया प्रीमियम देकर बीमा कराया जा सकता है और खुदा-न-ख्वास्ता दोनों हाथ कट जाते है या एक हाथ और एक पैर कट जाता है तो 12 हजार रुपये तक मिल जाता है । एक हाथ कट जाय तो 6 हजार तक मिल जाता है । यह बहुत अच्छी स्कीम है और कुछ एरियाज मे बहुत अच्छा काम कर रही है ।

It was pointed out that sugar price is rising in Delhi in these days. Here in Delhi, sugar price is always 10 paise more because there is a tax of ten paise per every kilo of sugar.

SHRI VAYALAR RAVI: It is rising every day (*Interruptions*).

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sugar price in Delhi, to my knowledge, is less than Rs. 3.0. I think it might be Rs. 2-90 or so, may be Rs 3 0 (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: No. It is more than that.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: No, it is wrong. People forget things very easily, especially the price of sugar which had been selling at Rs. 6 or Rs 5.50 per kilo before we assumed office. We were getting it at that rate. But now it has come down very low and it could not sustain at that price. Otherwise we would not be able to pay anything to the sugarcane growers. So, our efforts are that the price should remain some where at about Rs. 2.80 or 2.85 per kilo and we are trying to release more sugar so that the price comes down. So, with that, I have almost entirely covered the points.

MR. CHAIRMAN: Now, before I put the Demands to the vote of the House, I would like to know if any

(Shri Surjit Singh Barnala)

hon. Member wants to withdraw his cut motions.

SHRI P. RAJAGOPALA NAIDU: I seek leave of the House to withdraw or cut motions—Nos. 7 to 64, 67 to 90, 93 to 104, 107 to 111 and 114 to 117.

Cut motions Nos. 7 to 64, 67 to 90, 93 to 104, 107 to 111 and 114 to 117 were, by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Unless any hon. Member wishes any particular cut motion to be put separately, I will put all of them together.

SHRI A. K. ROY: I want my cut motions Nos. 406, 408 and 410 to be put separately to the vote of the House.

MR. CHAIRMAN: Except these three cut motions, I will put all other cut motions to the vote of the House.

Cut Motions Nos. 137 to 192, 194, 195, 197 to 203, 223 to 267, 296 to 368, 397 to 405, 407 and 409 were put and negatived

MR CHAIRMAN: I shall now put cut motion No. 406, moved by Shri A. K. Roy, to the vote of the House The question is:

"That the Demand under the head Department of Rural Development be reduced by Rs. 100.

['Need for setting up of public sector in agriculture with integrated State farming' (406)]".

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put Mr. Roy's Cut Motion No. 408 to the vote of the House. The question is: is:

"That the Demand under the head 'Department of Rural Development' be reduced by Rs. 100/-."

[Need for setting up of Land Army in the Blocks (408)].

The Lok Sabha divided:

Division No. 15] [15.57 hrs

AYES

*Bhadoria, Shri Arjun Singh
Damor, Shri Somjibhai
Roy, Shri A.K.

NOES

Balak Ram, Shri
Barnala, Shri Surjit Singh
Berwa, Shri Ram Kanwar
Chandan Singh, Shri
Chandravati Shrimati
Chaturvedi, Shri Shambhu Nath
Chaudhary, Shri Motibhai R.
Chauhan, Shri Bega Ram
Chhetri, Shri Chhatra Bahadur
Chowhan, Shri Bharat Singh
Deshmukh, Shri Ram Prasad
Dhillon, Shri Iqbal Singh
Dhurve, Shri Shyamlal
Ghosal, Shri Sudhir
Godara, Ch. Hari Ram Makkasar
Harikesh Bahadur, Shri
Heera Bhai, Shri
Hukam Ram, Shri
Jain, Shri Kacharulal Hemraj
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jasrotia, Shri Baldev Singh
Joshi, Dr. Murli Manohar
Kailash Prakash, Shri
Kaushik, Shri Purushottam
Khan, Shri Ghulam Muhammad
Khan, Shri Kanwar Mahmud Ali
Kundu, Shri Samrendra
Kureel, Shri R. L.
Lakshminarayanan, Shri M. R.
Liaquat Hussain, Shri Syed

*Wrongly voted for AYES

Limaye, Shri Madhu
Machhand, Shri Raghubir Singh
Mahala, Shri K. L.
Mahishi, Dr Sarojini
Maiti, Shrimati Abha
Mhalgi, Shri R. K.
Mishra Shri Janeshwar
Munda, Shri Kania
Negi, Shri T. S.
Paraste, Shri Dalpat Singh
Parmar, Shri Natwarlal B
Patil, Shri S D.
Pipli Shri Mohan Lal
Pradhan, Shri Gananath
Raghavji, Shri
Rai, Shri Gauri Shankar
Rajda, Shri Ratansinh
Ram Gopal Singh, Chawdhury
Ram Kishan, Shri
Ramachandran, Shri P.
Ramdas Singh, Shri
Ramji Singh, Dr.
Rathor, Dr Bhagwan Dass
Rodrigues, Shri Rudolph
Samantasinhera, Shri Padmacharan
Saran, Shri Daulat Ram
Sarkar, Shri S. K.
Shah, Shri Surath Bahadur
Sinha, Shri C. M.
Somani, Shri Roop Lal
Somani, Shri S. S.
Sukhendra Singh, Shri
Suraj Bhan, Shri
Tiwari, Shri Brij Bhushan
Ugrasen, Shri
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri Raghunath Singh
Yadav, Shri Ramjilal

MR. CHAIRMAN: Subject to correction, the result* of the Division is as follows.

Ayes—3,

Noes—68.

The Motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I now put Cut Motion No. 410 to the vote of the House.

The question is:

"That the Demand under the head 'Department of Rural Development' be reduced by Rs. 100/-."

[Failure in enforcing tillers' proprietorship on land. (410)"]

The Lok Sabha divided:

Division No 16].

[16 hrs

AYES

Bhagat Ram, Shri
Gawai, Shri D. G.
Halder, Shri Krishna Chandra
Joarder, Shri Dinesh
Kisku, Shri Jadunath
Kodiyan, Shri P. K.
Lakshminarayanan, Shri M. R.
Mahata, Shri C. R.
Mandal, Shri Makunda
Modak, Shri Bijoy
Pai, Shri T A.
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Saha, Shri A. K.
Saha, Shri Gadadhar
Shinde, Shri Annasaheb P.
Shiv Shanker, Shri P.
Tirkey, Shri Pius

NOES

Agrawal, Shri Satish
Balak Ram, Shri
Barnala, Shri Surjit Singh
Berwa, Shri Ram Kanwar
Bharat Bhushan, Shri

*The following members also recorded their votes: for NOES Shri Satish Agarwal, Shri Brij Lal Varma, Shri Ram Deo Singh, Shri Dharam Vir Vasisht, Shri Chhabiram Argal, Shri Bharat Bhushan and Shri Arjun Singh Bhadoria.

Chandan Singh, Shri
Chandravati, Shrimati
Chaturvedi Shri Shambhu Nath
Chaudhary, Shri Motibhai R.
Chauhan, Shri Bega Ram
Chhetri, Shri Chhatra Bahadur
Chowhan, Shri Bharat Singh
Deshmukh, Shri Ram Prasad
Dhilon, Shri Iqbal Singh
Dhurva, Shri Shyamlal
Ghosal, Shri Sudhir
Godara, Ch. Hari Ram Makkasar
Harikesh Bahadur, Shri
Heera Bhai, Shri
Hukam Ram, Shri
Jain, Shri Kacharulal Hemraj
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jasrotia, Shri Baldev Singh
Joshi, Dr. Murli Manohar
Kailash Prakash, Shri
Kaushik, Shri Purushottam
Khan, Shri Ghulam Mohammad
Khan, Shri Kanwar Mahmud Ali
Kundu, Shri Samarendra
Kureel, Shri R. L.
Liaquat Hussani Shri Syed
Limaye, Shri Madhu
Machhand, Shri Raghubir Singh
Mahala, Shri K. L.
Mahishi, Dr. Sarojini
Maiti, Shrimati Abha
Mhalgi, Shri R. K.
Mishra, Shri Janeshwar
Manda, Shri Karia
Nayak, Shri Laxmi Narain
Negi, Shri T. S.
Paraste, Shri Dalpat Singh
Parmar, Shri Natwarlal B.
Patil, Shri S. D.
Pipil, Shri Mohan Lal
Pradhan, Shri Gananath
Raghavji, Shri
Rai, Shri Gauri Shankar
Rajda, Shri Ratansinh
Ram Deo Singh, Shri
Ram Kishan, Shri
Ramachandran, Shri P.
Ramdas Singh, Shri
Rathor, Dr. Bhagwan Das
Samantasinhera, Shri Padmacharan
Saran, Shri Daulat Ram
Sarkar Shri S. K.
Shah Shri Surath Bahadur
Shastri Shri Y. P.
Sinha Shri C. M.
Somani Shri Roop Lal
Somani Shri S. S.
Sukhendra Singh Shri
Suraj Bhan Shri
Tiwari Shri Brij Bhushan
Varma, Shri Ravindra
Vasisht, Shri Dharma Vir
Verma, Shri Brij Lal
Verma, Shri Raghunath Singh
Yadav, Shri Ramjilal

MR. CHAIRMAN: Subject to correction, the result* of the division is as follows:

Ayes : 18;

Noes : 70.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put the Demands for Grants to the vote of the House. The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums neces-

*The following Members also recorded their votes for NOES:

Dr. Ramji Singh, Chaudhary Ram Gopal Singh, Shri Arjun Singh Bhadoria and Shri Chhabiram Argal

sary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1980, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 10 relating to the 'Ministry of Agriculture and Irrigation'."

The motion was adopted.

Demands for Grants, 1979-80 in respect of the Ministry of Agriculture and Irrigation voted by Lok Sabha

No of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16-3-1979		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs'.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
	Ministry of Agriculture and Irrigation				
1	Department of Agriculture .	42,01,000	..	2,10,05,000	..
2	Agriculture . . .	23,94,61,000	107,67,99,000	119,73,05,000	538,39,96,000
3	Fisheries	4,80,20,000	5,13,94,000	24,01,02,000	25,69,71,000
4	Animal Husbandry and Dairy Development . . .	15,34,36,000	3,94,32,000	76,71,81,000	19,71,63,000
5	Forest	6,23,63,000	79,00,000	31,18,14,000	3,94,99,000
6	Department of Food . .	95,45,72,000	7,90,48,000	477,28,62,000	39,52,42,000
7	Department of Rural Development	59,95,21,000	4,39,11,000	299,76,07,000	21,95,57,000
8	Department of Agricultural Research and Education	1,70,000	..	8,50,000	..
9	Payments to Indian Council of Agricultural Research	14,63,50,000	..	73,17,48,000	..
10	Department of Irrigation .	5,45 85,000	1,27,09,000	27,29,24,000	6,35,43,00

16.02 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS, 1979-80

MINISTRY OF ENERGY

MR. CHAIRMAN: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 28 to 30 relating to the Ministry of Energy for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President

*Moved with the recommendation of the President.